

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2005—वैशाख 23, शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 7-9/04/1/6.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-10-2004 के कंडिका-2 में प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में 09 जिले सम्मिलित किये गये हैं. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5-1-2005 में लिए गए निर्णय अनुसार जिला धमतरी को अनुक्रमांक 10 के रूप में सम्मिलित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक ई-7/16/2004/1/2.—डॉ. एच. एल. प्रजापति, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 24-5-2005 से 7-6-2005 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 21, 22 एवं 23-5-2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. प्रजापति, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में डॉ. प्रजापति, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. प्रजापति, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

क्रमांक ई-7/23/2004/1/2.—श्री एस. के. कुजूर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 19-5-2005 से 1-6-2005 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री कुजूर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 8-3/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस्पात गोदावरी लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर के बायलर क्रमांक सी.जी./33 को निम्नलिखित शर्तों पर ठक अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 26-4-2005 से दिनांक 30-6-2005 तक की छूट प्रदान करता है :—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।

- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है।

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 8-11/2004/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पूर्व), कोरबा के बायलर क्रमांक एम.पी./3210 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 11-4-2005 से दिनांक 10-7-2005 तक तीन माह की छूट प्रदान करता है :—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखो, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्रमांक /980/एफ 9-17/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पाटन, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :—

अनुसूची

पाटन निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम दैवमोर, बठेना, सिकोला एवं सुपकान्हा, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
- पूर्व में : ग्राम सुपकान्हा, सोनपुर एवं खमरिया, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
- दक्षिण में : ग्राम खमरिया, अटारी, अखरा एवं पंदर, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
- पश्चिम में: ग्राम पंदर एवं दैवमोर, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्रमांक /983/एफ 9-18/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चारामा, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :—

अनुसूची

चारामा (जिला-कांकेर) निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम कन्डेल, माहुद एवं भेलाई, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
- पूर्व में : ग्राम भेलाई, तेलगुड़ा, भिरोद, करंजैसा, सिरसिदा, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
- दक्षिण में : ग्राम करंजैसा, सिरसिदा, गिरहोला, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
- पश्चिम में: ग्राम सिरसिदा, दरगहन, चारामा, गिरहोला, कन्डेल एवं माहुद, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्रमांक /986/एफ 9-6/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चिरमिरी, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :—

अनुसूची

चिरमिरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम लाई एवं हरा, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
- पूर्व में : ग्राम हरा, दरीटोला, लोहारी, नवापारा, मोरगा, सरगोका, पश्चिम चिरमिरी कालरी, कोरिया-कालरी, उत्तर चिरमिरी कालरी एवं डोमनहिल कालरी, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
- दक्षिण में : ग्राम डोमनहिल कालरी, दुपछोला एवं भण्डरदेई, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
- पश्चिम में: ग्राम भण्डरदेई, भुकभुकी, चिरमिरी कालरी, खुरासिया कालरी, एन.सी.पी.एच. कालरी, सरभोका, सीरियाखोह एवं लाई, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्रमांक /989/575/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए डभरा, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :—

अनुसूची

डभरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम कुसुमझर, कतगन, छुईपाली, कटेकोनीछोटे, हरदीडीह एवं ठाकुरपाली, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
- पूर्व में : ग्राम कटेकोनीछोटे, ठाकुरपाली, हरदीडीह, चुराघाट, भेंडीकोना एवं सकराली, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
- दक्षिण में : ग्राम सकराली, उपनी, नवापारा एवं बसंतपुर, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
- पश्चिम में: ग्राम बसंतपुर, कुसुमझर एवं कतगन, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2005

क्रमांक /स.क.वि./2005/793.—राज्य शासन निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 60 के अंतर्गत श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, ललिता चौक, बड़ई पारा, रायपुर को अवैतनिक रूप से आयुक्त, निःशक्तजन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुजूर, सचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जांजगीर | गतवा प. ह. नं. 26 | 0.890 | कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.). | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गतवा से केराकछार निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 418/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | दुर्ग | डुन्देरा | 0.42 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग क्रमांक-2 (भ./स.), दुर्ग. | उतई, उमरपोंटी, डुन्देरा सड़क निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 421/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|--|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | धमधा | करेली | 0.37 | कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग. | कोकड़ी जलाशय |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 424/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|---|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | धमधा | बसनी | 1.31 | कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग. | कोकड़ी जलाशय |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 427/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|---|-------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | धमधा | कोकड़ी | 2.60 | कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग. | कोकड़ी जलाशय |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 430/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|---|---------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | धमधा | कोकड़ी | 0.62 | कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग. | कोकड़ी जलाशय की उलट |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 442/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|---|-----------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | धमधा | सिरनाभाठा | 0.58 | कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग. | टेंगना नाला व्यपवर्तन |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 अप्रैल 2005

रा. प्र. क्र. 2 अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सूरजपुर | सोनपुर | 2.37 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सूरजपुर, सरगुजा. | सोनपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अप्रैल 2005

रा. प्र. क्र. 3 अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------|----------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सूरजपुर | ब्रजनगर | 0.19 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अंबिकापुर (छ. ग.). | लटोरी कल्याणपुर मार्ग पर गलफुल्ली सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 मार्च 2004

क्रमांक 1226/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|----------------------------|------------|-----------|----------------------------------|--|-------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा | दन्तेवाड़ा | धुरली | 10.183 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा. | बासनपुर व्यपवर्तन योजना |

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 मार्च 2004

क्रमांक 1227/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|----------------------------|------------|-----------|----------------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा | दन्तेवाड़ा | पोटाली | 3.075 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) दक्षिण बस्तर संभाग, दन्तेवाड़ा. | अरनपुर से माड़ेंदा पहुंच मार्ग निर्माण. |

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 मार्च 2004

क्रमांक 1432/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|----------------------------|------------|-----------|----------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा | दन्तेवाड़ा | गीदम | 1.158 | मेजर कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, केम्प कारली. | राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ी- करण एवं सुदृढ़ीकरण. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्टा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक-13/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | पेण्डारोड | पेण्डा | 2.00 | उप संचालक, मत्स्योद्योग बिलासपुर. | मत्स्य बीज उत्पादन इकाई |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/1717/भू-अर्जन/05/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | नवागांव | 2.29 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी. | बेलर गांव जलाशय के अंतर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु. |

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/1721/भू-अर्जन/15/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | कसपुर | 5.06 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी. | सीतानदी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत कसपुर माइनर नहर निर्माण हेतु. |

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/06/अ/82 वर्ष 04-05/1725.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | मोहमल्ला | 2.64 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी. | मोहमल्ला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ/82 वर्ष 04-05/1730.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | सरईटोला | 2.76 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी. | बटनहरा जलाशय क्रमांक-2 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. |

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ/82 वर्ष 04-05/1734.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | भूमका | 1.02 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी. | बेलरगांव जलाशय के अंतर्गत भूमका माइनर नहर निर्माण हेतु. |

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ/82 वर्ष 04-05/1738.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-------------|------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | गट्टासिल्ली | 4.44 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी. | बटनहरा जलाशय क्रमांक-2 के नहर निर्माण हेतु. |

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/13/अ/82 वर्ष 04-05/1742.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | नवागांव | 3.94 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी. | सीतानदी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नवागांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु. |

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/14/अ/82 वर्ष 04-05/1746.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-----------|------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| धमतरी | नगरी | नवागांव | 2.43 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी. | सीतानदी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत कसपुर माइनर नहर निर्माण हेतु. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 2686/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|--------------------|------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | छुईखदान | संडी प.ह.नं. 16 | 53.39 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान. | पंडरिया जलाशय के अंतर्गत डूबान उलट एवं बांध पार निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 2688/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | छुईखदान | मानपुर पहाड़ी प.ह.नं. 5 | 12.45 | कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान. | कोलारनाला टारबांध के अंतर्गत डूबान क्षेत्र. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 2691/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|---------------------|------------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | छुईखदान | मानपुर प.ह.नं. 8 | 2.46 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान. | जीराटोला जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर बायीं तट नहर. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 2692/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | छुईखदान | जीराटोला प.ह.नं. 7 | 39.27 | कार्यालय यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान. | जीराटोला जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर बायीं तट एवं दायीं तट नहर तथा डुबान. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1404 क/भू-अर्जन/21/अ/82 वर्ष 04-05/—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-तिर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 1 | 0.18 |
| 7 | 0.25 |
| 30 | 0.05 |
| 84 | 0.15 |
| 80 | 0.04 |
| 3 | 0.04 |
| 55 | 0.13 |
| 53 | 0.08 |
| योग | 8 |
| | 0.92 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रविशंकर सागर
जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी
के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन विशेष-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़,
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक 2 -अ 82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुर, प. ह. नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.37 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 1343 | 0.06 |
| 1348/1 | 0.05 |
| 1759 | 0.25 |
| 1344/2 | 0.01 |
| 1346 | 0.01 |
| 1347 | 0.01 |
| 1349 | 0.03 |
| 1371 | 0.03 |
| 1722 | 0.03 |
| 1756 | 0.12 |
| 1784 | 0.08 |
| 1958 | 0.05 |
| 1725 | 0.05 |
| 1824 | 0.03 |
| 1728 | 0.02 |
| 1731 | 0.01 |
| 1730 | 0.04 |
| 1732 | 0.02 |
| 1817 | 0.03 |
| 1757 | 0.02 |
| 1783 | 0.02 |

(1) (2)

| | |
|-----------|------|
| 1785 | 0.04 |
| 1820 | 0.08 |
| 1796 | 0.07 |
| 1801 | 0.16 |
| 1797 | 0.07 |
| 1819 | 0.04 |
| 1802 | 0.24 |
| 1816 | 0.01 |
| 1823 | 0.09 |
| 1830 | 0.15 |
| 1908 | 0.01 |
| 1909 | 0.03 |
| 1910 | 0.04 |
| 1912 | 0.02 |
| 1913 | 0.07 |
| 1914 | 0.03 |
| 1915 | 0.03 |
| 1917 | 0.04 |
| 1918 | 0.03 |
| 1824/2539 | 0.15 |

योग. 41 2.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 जनवरी 2005

क्रमांक 38.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.465 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 1/3 | 0.255 |
| 1/2 | 0.008 |
| 2/2 | 0.028 |
| 2/1 | 0.032 |
| 2/4 | 0.146 |
| 2/3 | 0.077 |
| 7 | 0.178 |
| 8/1 | 0.267 |
| 9/4 | 0.045 |
| 9/3 | 0.125 |
| 9/1 | 0.012 |
| 10/1 | 0.069 |
| 10/2 | 0.053 |
| 11/1 | 0.028 |
| 11/2 | 0.036 |
| 13 | 0.008 |
| 12 | 0.008 |
| 14 | 0.089 |

योग 18 1.465

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

प्र. क्र. 5/अ-82/2004-2005. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.668 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

2/2, 3/2

0.150

2/1, 3/1

0.150

5, 7, 8

0.160

462/1

0.015

461

0.175

455/4, 457

0.075

455/1

0.045

456, 455/3

0.040

455/2

0.080

453/1

0.040

453/2

0.110

432/1

0.180

419, 420

0.080

716

0.004

736/2

0.015

421, 422/2

0.160

637/1

0.040

740

0.350

641

0.030

665/1

0.004

703/1

0.030

668

0.030

669, 670

0.090

426

0.055

(1)

(2)

449/2

0.004

423, 424, 630

0.130

662, 663, 686

0.130

687

0.025

688

0.055

701/1

0.200

703/2

0.006

739/2

0.080

734

0.130

735

0.080

606

0.040

747/1

0.080

676/1

0.050

676/2

0.035

676/3

0.030

702

0.004

671

0.016

739/1

0.080

701/3

0.050

703/3

0.004

703/4

0.004

703/5

0.030

683/4

0.030

703/6

0.030

633/6

0.035

633/9

0.045

634, 635

0.040

417, 418

0.105

689

0.012

योग

53

3.668

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2 × 250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ पाईपलाइन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

(1)

(2)

प्र. क्र. 6/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-छिरहुट, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.487 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

| | |
|-------|-------|
| 141/2 | 0.405 |
| 146/2 | 0.073 |
| 147 | 0.259 |
| 148/1 | 0.077 |
| 148/2 | 0.194 |
| 149 | 0.506 |
| 159 | 0.101 |
| 160 | 0.113 |
| 150/2 | 0.437 |
| 152 | 0.081 |
| 158 | 0.053 |
| 153 | 0.113 |
| 137 | 0.101 |
| 24/4 | 0.049 |
| 143/1 | 0.202 |
| 24/5 | 0.781 |
| 145 | 0.340 |
| 142/1 | 0.130 |
| 142/2 | 0.045 |
| 157/1 | 0.101 |
| 24/2 | 0.081 |
| 162 | 0.186 |
| 143/2 | 0.202 |
| 144/2 | 0.040 |
| 138 | 0.729 |

| | |
|-------|-------|
| 139 | 0.004 |
| 140 | 0.348 |
| 146/1 | 0.040 |
| 161/2 | 0.271 |
| 136/1 | 0.210 |
| 136/2 | 0.210 |
| 24/3 | 0.061 |
| 157/2 | 0.563 |
| 156 | 0.134 |
| 150/3 | 0.040 |
| 161/1 | 0.202 |

योग

26

7.487

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2 × 250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

प्र. क्र. 7/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.588 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

60/2

0.024

| (1) | (2) |
|--------------|----------|
| 63/2 | 0.150 |
| 66 | 0.004 |
| 61 | 0.055 |
| 90/1 | 0.035 |
| 62 | 0.035 |
| 63/1 | 0.035 |
| 55, 79/2 | 0.170 |
| 41 | 0.210 |
| 93 | 0.070 |
| 99 | 0.020 |
| 102/1 | 0.194 |
| 108, 112/1 क | 0.004 |
| 102/2 | 0.105 |
| 102/4 | 0.364 |
| 97 | 0.006 |
| 98 | 0.004 |
| 60/1 | 0.050 |
| 60/3 | 0.010 |
| 90/2 | 0.025 |
| 71 | 0.004 |
| 58/1 | 0.008 |
| 59 | 0.006 |
| योग | 20 1.588 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2 × 250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ पाईपलाइन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

प्र. क्र. 8/अ-82/2004-2005. —चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-डोडकधारी, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.463 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

| | |
|---------|-------|
| 140 | 0.223 |
| 141 | 0.121 |
| 141/2 | 0.040 |
| 142 | 0.227 |
| 143/1 घ | 0.024 |
| 143/1 ङ | 0.243 |
| 143/1 ख | 0.243 |
| 144 | 0.174 |
| 145 | 0.267 |
| 149 | 0.016 |
| 150/3 | 0.085 |
| 156/3 | 0.040 |
| 161/6 | 0.138 |
| 168 | 0.049 |
| 169 | 0.267 |
| 181/2 | 0.081 |
| 146 | 0.057 |
| 154 | 0.073 |
| 150/1 | 0.251 |
| 147 | 0.283 |
| 148 | 0.194 |
| 156/2 | 0.445 |
| 158/2 | 0.170 |
| 161/1 | 0.222 |
| 191/6 | 0.162 |
| 193/3 | 0.069 |
| 155/1 | 0.036 |
| 157/2 | 0.040 |
| 161/2 | 0.268 |
| 160/1 | 0.263 |
| 160/3 | 0.142 |
| 164 | 0.061 |
| 176 | 0.121 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|---------|-------|
| 180 | 0.012 | 143/1 ग | 0.170 |
| 169/1 | 0.150 | 184 | 0.113 |
| 168/3 | 0.016 | 161/3 | 0.134 |
| 185 | 0.125 | 186 | 0.340 |
| 165 | 0.652 | 33/1 ख | 0.032 |
| 166 | 0.312 | 156/4 | 0.146 |
| 194 | 0.870 | 156/5 | 0.162 |
| 196/2 | 0.105 | 156/6 | 0.049 |
| 167 | 0.283 | 193/1 | 0.142 |
| 174/1 क | 0.882 | 155/2 | 0.134 |
| 174/1 घ | 0.105 | 157/1 | 0.036 |
| 169/2 | 0.061 | 158/1 | 0.134 |
| 175 | 0.243 | 159 | 0.032 |
| 170 | 0.243 | 161/12 | 0.125 |
| 171/1 | 0.065 | 169/5 | 0.162 |
| 172 | 0.219 | 160/2 | 0.138 |
| 182 | 0.073 | 161/4 | 0.129 |
| 183 | 0.073 | 178/3 | 0.089 |
| 173/1 | 0.369 | 161/5 | 0.113 |
| 173/2 | 0.142 | 161/7 | 0.065 |
| 177 | 0.243 | 161/8 | 0.105 |
| 150/2 | 0.065 | 150/4 | 0.101 |
| 174/1 ड | 0.049 | 161/9 | 0.299 |
| 187/1 | 0.178 | 161/10 | 0.068 |
| 187/2 | 0.081 | 163/1 | 0.134 |
| 191/2 क | 0.024 | 161/11 | 0.295 |
| 191/3 | 0.040 | 163/2 | 0.040 |
| 143/1 क | 0.235 | 171/2 | 0.040 |
| 188 | 0.267 | 171/4 | 0.274 |
| 189 | 0.097 | 171/3 | 0.328 |
| 190 | 0.214 | 171/5 | 0.405 |
| 191/4 | 0.016 | 173/3 | 0.125 |
| 191/1 ख | 0.024 | 178/1 | 0.251 |
| 191/1 ग | 0.061 | 178/2 | 0.105 |
| 192 | 0.243 | 191/1 क | 0.417 |
| 195/1 | 0.255 | 191/2 ख | 0.121 |
| 196/3 | 0.109 | 193/2 | 0.162 |
| 174/1 ख | 0.061 | 161/13 | 0.141 |
| 174/2 ग | 0.053 | 161/14 | 0.053 |
| 176 | 0.656 | 161/15 | 0.085 |
| 191/5 | 0.324 | 193/4 | 0.101 |
| 181/1 | 0.291 | 196/1 | 0.283 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--|----------------|-------|-------|
| 150/5 | 0.121 | 259 | 0.004 |
| 157/3 | 0.036 | 301 | 0.348 |
| 157/4 | 0.081 | 78 | 0.142 |
| 195/2 | 0.166 | 260 | 0.186 |
| | | 300/2 | 0.024 |
| योग | 110 | 300/3 | 0.040 |
| | 20.463 | 214 | 0.036 |
| | | 217 | 0.170 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम | | 218 | 0.065 |
| ताप विद्युत गृह 2 × 250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ बांध का | | 227 | 0.077 |
| निर्माण. | | 228 | 0.085 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी | | 253 | 0.016 |
| (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया | | 254 | 0.073 |
| जा सकता है. | | 255 | 0.032 |
| | | 240 | 0.020 |
| कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005 | | 241 | 0.125 |
| प्र. क्र. 9/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का | | 246/1 | 0.113 |
| समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि | | 300/1 | 0.275 |
| की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए | | 302/3 | 0.032 |
| आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् | | 302/1 | 0.336 |
| 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत | | 314 | 0.089 |
| इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन | | 318/1 | 0.304 |
| के लिए आवश्यकता है :— | | 327 | 0.032 |
| | | 328/1 | 0.138 |
| | | 325 | 0.032 |
| | | 329/3 | 0.368 |
| | | 213 | 0.040 |
| | | 224 | 0.202 |
| (1) भूमि का वर्णन— | | 307/2 | 0.032 |
| (क) जिला-कोरबा | | 312/3 | 0.073 |
| (ख) तहसील-कटघोरा | | 313/3 | 0.012 |
| (ग) नगर/ग्राम-बिरबट, प. ह. नं. 29 | | 316/4 | 0.085 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.220 हेक्टेयर | | 316/7 | 0.024 |
| | | 326 | 0.081 |
| खसरा नम्बर | रकबा | 222 | 0.129 |
| | (हेक्टेयर में) | 236 | 0.020 |
| (1) | (2) | 238 | 0.012 |
| -77 | 0.146 | 245 | 0.227 |
| 220 | 0.024 | 250 | 0.045 |
| 215 | 0.057 | 223 | 0.061 |
| 216 | 0.016 | 229/2 | 0.081 |
| 221 | 0.012 | 230/3 | 0.032 |
| 258 | 0.016 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|------------|
| 231 | 0.012 | 313/2 | 0.016 |
| 233/3 | 0.162 | 316/6 | 0.024 |
| 229/1 | 0.028 | 329/2 | 0.194 |
| 230/2 | 0.194 | 323/1 | 0.765 |
| 232 | 0.040 | 324 | 0.020 |
| 233/2 | 0.121 | 320/2 | 0.494 |
| 249 | 0.263 | 320/1 | 0.243 |
| 257/3 | 0.150 | 211 | 0.016 |
| 303 | 0.267 | 226 | 0.069 |
| 233/1 | 0.040 | 225/1 | 0.040 |
| 233/4 | 0.121 | 235 | 0.186 |
| 234 | 0.352 | 251 | 0.223 |
| 257/2 | 0.210 | 252 | 0.073 |
| 257/4 | 0.138 | 246/2 | 0.121 |
| 237 | 0.073 | 300/4 | 0.231 |
| 239 | 0.020 | 318/2 | 0.300 |
| 304/1 | 0.158 | 328/2 | 0.105 |
| 316/3 | 0.154 | 302/2 | 0.206 |
| 229/1 | 0.356 | 304/2 | 0.206 |
| 333 | 0.012 | 307/3 | 0.057 |
| 242 | 0.024 | 308/2 | 0.053 |
| 244 | 0.150 | 312/4 | 0.073 |
| 305 | 0.632 | 313/4 | 0.024 |
| 306 | 0.024 | 316/5 | 0.077 |
| 230/1 | 0.341 | 316/8 | 0.024 |
| 256 | 0.109 | 329/4 | 0.194 |
| 257/1 | 0.138 | 316/2 | 0.251 |
| 212 | 0.154 | 310 | 0.016 |
| 309 | 0.081 | 321 | 0.316 |
| 311 | 0.020 | 247 | 0.283 |
| 332 | 0.450 | 248 | 0.008 |
| 312/1 | 0.073 | 225/2 | 0.122 |
| 316/1 | 0.024 | | |
| 313/1 | 0.016 | | |
| 315 | 0.543 | | |
| 317 | 0.129 | | |
| 319 | 0.178 | | |
| 322 | 0.129 | | |
| 323/2 | 0.263 | | |
| 307/1 | 0.057 | | |
| 307/4 | 0.053 | | |
| 308/1 | 0.069 | | |
| 312/2 | 0.073 | | |
| | | योग | 105 16.220 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2 × 250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा,
छत्तीसगढ़, एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 1072/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
(ख) तहसील-दंतेवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम-टेकनार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.30 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 2 | 0.02 |
| 14 | 0.07 |
| 53 | 0.25 |
| 105 | 0.13 |
| 173 | 0.04 |
| 780 | 0.05 |
| 782 | 0.25 |
| 958 | 0.26 |
| 980 | 0.07 |
| 986 | 0.10 |
| 993 | 0.12 |
| 996 | 0.08 |
| 1117 | 0.30 |
| 1231 | 0.08 |
| 1139 | 0.23 |
| 10 | 0.12 |
| 17 | 0.40 |
| 63 | 0.05 |
| 109 | 0.16 |
| 1137 | 0.06 |

| (1) | (2) |
|------|------|
| 783 | 0.02 |
| 846 | 0.12 |
| 983 | 0.02 |
| 981 | 0.10 |
| 994 | 0.05 |
| 995 | 0.06 |
| 1107 | 0.03 |
| 1118 | 0.18 |
| 1236 | 0.53 |
| 1142 | 0.16 |
| 40 | 0.05 |
| 35 | 0.06 |
| 29 | 0.10 |
| 175 | 0.13 |
| 1138 | 0.07 |
| 784 | 0.15 |
| 957 | 0.10 |
| 960 | 0.18 |
| 982 | 0.12 |
| 987 | 0.07 |
| 1002 | 0.18 |
| 1115 | 0.16 |
| 1230 | 0.05 |
| 1244 | 0.20 |
| 1143 | 0.12 |
| 1245 | 0.28 |
| योग | 6.30 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कारली, भैरमगढ़ एवं आवराभाटा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दंतेवाड़ा एवं कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2005

क्रमांक 1184/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

दन्तेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2005

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-बीजापुर
(ग) नगर/ग्राम-कोतापाल, प.ह.नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.854 हेक्टेयर

क्रमांक 1187/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

| | |
|--------|-------|
| 108/1 | 0.243 |
| 108/2 | 0.105 |
| 112/2 | 0.203 |
| 113/2 | 0.121 |
| 532/2 | 0.186 |
| 529/1 | 0.182 |
| 529/2 | 0.182 |
| 529/3 | 0.186 |
| 510/2 | 0.093 |
| 510/3 | 0.093 |
| 510/4 | 0.093 |
| 508 | 0.110 |
| 506 | 0.121 |
| 505/5 | 0.138 |
| 505/4 | 0.142 |
| 58 | 0.445 |
| 62 | 0.162 |
| 63 | 0.389 |
| 67/2 | 0.081 |
| 66 | 0.049 |
| 65 | 0.061 |
| 69/1 | 0.121 |
| 71 | 0.101 |
| 70 | 0.151 |
| 85/2 | 0.097 |
| 37 | 0.121 |
| 38 | 0.162 |
| 43/137 | 0.020 |
| 41/1 | 0.348 |
| 24/1 | 0.081 |
| 44/1 | 0.242 |

योग

31

4.854

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-बीजापुर
(ग) नगर/ग्राम-कोतापाल, प.ह.नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.218 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

| | |
|--------|-------|
| 4/1 | 0.182 |
| 4/2 | 0.182 |
| 4/238 | 1.004 |
| 8/1 ख | 0.810 |
| 8/2 ख | 0.243 |
| 52/2 | 0.854 |
| 49/1 | 2.219 |
| 49/3 | 3.441 |
| 47 | 0.599 |
| 49/2 | 0.745 |
| 49/4 | 0.543 |
| 58 | 0.162 |
| 50 | 0.211 |
| 8/1 | 2.429 |
| 51/1 | 1.781 |
| 51/2 क | 0.615 |
| 57/1 | 0.105 |
| 52/2 ख | 0.854 |
| 51/2 ख | 0.615 |
| 57/2 | 0.105 |
| 52/2 क | 0.854 |
| 54/1 | 0.405 |
| 8/2 | 0.810 |
| 54/2 | 0.466 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोतापल्ली, जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|--------|--------|-------|
| 8/3 | 1.134 | 1078 | 0.020 |
| 16/1 | 0.202 | 1080/1 | 0.291 |
| 103 | 0.494 | 1083 | 0.085 |
| 104 | 0.049 | 1111/3 | 0.162 |
| 3 | 0.659 | 1115 | 0.291 |
| 87/3 | 0.405 | 1116 | 0.133 |
| 87/2 | 0.405 | 1134 | 0.222 |
| 55 | 0.202 | 1133 | 0.093 |
| 467 | 0.186 | 1144 | 0.230 |
| 106 | 0.247 | 1137 | 0.020 |
| योग | 34 | 1138 | 0.170 |
| | 24.218 | 1139 | 0.200 |
| | | 1238 | 0.376 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोत्तापाल, जलाशय निर्माण हेतु. | | 763 | 0.445 |
| | | 786 | 0.097 |
| | | 788 | 0.145 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है. | | 705/2 | 0.080 |
| | | 816 | 0.024 |

दंतेवाड़ा, दिनांक 22 मार्च 2005

योग 3.718

क्रमांक 1516 क/भू. अ./अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-दंतेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बालूद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.718 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 801 | 0.141 |
| 1056 | 0.368 |
| 1055 | 0.125 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोडरे व्यपवर्तन बालूद हेतु मुख्य/शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्टा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर,
छत्तीसगढ़, एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बस्तर जिला
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-मुंजला, प.ह.नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.984 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 25 | 0.060 |
| 30 | 0.080 |
| 55 | 0.056 |
| 54 | 0.112 |
| 60 | 0.072 |
| 58 | 0.012 |
| 65 | 0.112 |
| 64 | 0.012 |
| 67 | 0.016 |
| 69 | 0.284 |
| 86 | 0.132 |
| 85 | 0.028 |
| 84 | 0.008 |
| योग | 0.984 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चपका वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/03-04/21/04. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बस्तर जिला
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प.ह.नं. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.612 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 1312 | 0.156 |
| 1456 | 0.208 |
| 1457 | 0.080 |
| 1458 | 0.144 |
| 1461 | 0.024 |
| योग | 0.612 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चपका वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/03-04/21/04. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बस्तर जिला
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-नगरनार, प.ह.नं. 51
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 148/3 | 0.02 |
| 148/2 | 0.06 |
| 149/1 | 0.03 |
| 149/3 | 0.16 |
| 162 | 0.19 |
| योग | 0.46 |

| (1) | (2) |
|-----|------|
| 11 | 0.40 |
| योग | 0.63 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भालुगुडा उदवहन सिंचाई योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/03-04/21/04. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/03-04/21/04. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कस्तुरी, प.ह.नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 हेक्टेयर

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नगरनार, प.ह.नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 10 | 0.23 |

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 304 | 0.02 |
| 303 | 0.18 |
| 302/2 | 0.03 |
| 302/3 | 0.04 |
| 310 | 0.07 |
| 311 | 0.10 |
| 317 | 0.06 |
| 318 | 0.05 |

| (1) | (2) |
|-------|------|
| 322 | 0.08 |
| 339 | 0.02 |
| 323 | 0.11 |
| 324 | 0.22 |
| 245 | 0.11 |
| 326 | 0.11 |
| 325/1 | 0.04 |
| 325/2 | 0.10 |
| 336 | 0.15 |
| 217/1 | 0.04 |
| 337 | 0.05 |
| 338 | 0.03 |
| 248 | 0.03 |
| 239/1 | 0.13 |
| 241/1 | 0.10 |
| 233 | 0.09 |
| 225 | 0.07 |
| 218/1 | 0.03 |
| 218/2 | 0.04 |
| 218/3 | 0.03 |
| 217/2 | 0.16 |
| योग | 2.29 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भालुगुडा उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ-82/03-04/21/04. —चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े आमाबाल, पं.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.900 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 1684 | 0.172 |
| 1685 | 0.016 |
| 1781 | 0.176 |
| 1809 | 0.084 |
| 1810 | 0.068 |
| 1811 | 0.020 |
| 1823/1 | 0.056 |
| 1824 | 0.040 |
| 1825 | 0.044 |
| 1827/1 | 0.044 |
| 1826/1 | 0.008 |
| 1828 | 0.048 |
| 1830/1 | 0.048 |
| 1830/2 | 0.020 |
| 1750 | 0.020 |
| 1831 | 0.036 |
| योग | 0.900 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत आमाबाल वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/03-04/21/04. —चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चमिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.114 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) | (1) | (2) |
|------------|------------------------|-----|-------|
| (1) | (2) | | |
| | | 443 | 0.224 |
| | | 459 | 0.268 |
| 283 | 0.114 | 466 | 0.312 |
| | | 472 | 0.156 |
| योग | 0.114 | 474 | 0.240 |
| | | 444 | 0.088 |
| | | योग | 3.225 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत सोनारपाल वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/9/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तारागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.225 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 169 | 0.324 |
| 170 | 0.240 |
| 184 | 0.088 |
| 186 | 0.348 |
| 437 | 0.180 |
| 439 | 0.067 |
| 447 | 0.234 |
| 446 | 0.456 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत सोनारपाल वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/12/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे आमबाबाल, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.036 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 537 | 0.100 |
| 555 | 0.056 |
| 552 | 0.016 |
| 553 | 0.080 |

| (1) | (2) | अनुसूची | |
|----------|-------|-----------------------------------|----------------|
| 561 | 0.056 | (1) भूमि का वर्णन- | |
| 562 | 0.024 | (क) जिला-बस्तर जिला | |
| 563 | 0.076 | (ख) तहसील-जगदलपुर | |
| 568 | 0.044 | (ग) नगर/ग्राम-सोनारपाल | |
| 590 | 0.048 | (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.889 हेक्टेयर | |
| 589 | 0.048 | खसरा नम्बर | रकबा |
| 592, 595 | 0.096 | | (हेक्टेयर में) |
| 593 | 0.010 | (1) | (2) |
| 599 | 0.100 | 4 | 0.516 |
| 601 | 0.108 | 17/2 | 0.180 |
| 618 | 0.022 | 18 | 0.216 |
| 617 | 0.036 | 20/3 | 0.363 |
| 616 | 0.244 | 102/1 | 0.016 |
| 615/2 | 0.072 | 103/2 | 0.138 |
| 623 | 0.072 | 103/3 | 0.162 |
| 624/1 | 0.080 | 103/4 | 0.216 |
| 624/2 | 0.068 | 140/1, 141/1, 141/2 | 0.264 |
| 404 | 0.172 | 141/8 | 0.124 |
| 402 | 0.044 | 141/9 क, 141/10 | 0.084 |
| 381/1 | 0.044 | 141/9 ग | 0.048 |
| 282 | 0.160 | 141/11 क | 0.136 |
| 384 | 0.160 | 190/6 क | 0.428 |
| योग | 2.036 | 190/27 क | 0.160 |
| | | 190/36 क | 0.061 |
| | | 2/4, 141/7 | 0.110 |
| | | 215/1 | 0.304 |
| | | 215/2 | 0.200 |
| | | 216 | 0.265 |
| | | 217 | 0.240 |
| | | 224 | 0.021 |
| | | 210/5 | 0.186 |
| | | 190/20 | 0.222 |
| | | 225/1 | 0.162 |
| | | 210/1 | 0.336 |
| | | 219/3 | 0.353 |
| | | 190/35 | 0.124 |
| | | 148 | 0.050 |
| | | 212/1 | 0.021 |
| | | 211/1 क | 0.183 |
| | | योग | 5.889 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत आमबाबल वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक कं/भू-अर्जन/11/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत सोनारपाल वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/04-05/10/05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बस्तर जिला
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-अघनपुर, प. ह. नं. 06 (अ)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.03 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---------------------|---------------------------|
| 26/1 | 3.48 |
| 26/4 | 3.50 |
| 91/1/1 | 0.99 |
| 91/1/2 | 0.99 |
| 91/1/3 | 0.99 |
| 91/1, 95/1 | 4.44 |
| 93 | 2.00 |
| 94/1 | 0.72 |
| 94/3 | 0.72 |
| 96 | 3.40 |
| 112/1 ड/1 | 0.41 |
| 112/1 ड/2 | 0.25 |
| 112/1 क, 112/1 ल/टू | 0.40 |
| 112/1 क, 112/1 ल/टू | 1.50 |
| 112/1 क, 112/1 ल/टू | 0.40 |
| 112/1 क, 112/1 ल/टू | 1.00 |
| 112/1 क, 112/1 ल/टू | 0.79 |
| 112/1 क, 112/1 ल/टू | 0.54 |
| 94/2 | 0.71 |
| 112/1 क, 112/1 ल/टू | 0.80 |
| योग | 28.03 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आवासीय भवन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन अतिरिक्त-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2005

क्रमांक 73/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-धोठवानी, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.32 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|-------------------|-------------------------------|
| 74 | 0.12 |
| 73 | 0.12 |
| 90/1 | 0.06 |
| 90/2 | 0.15 |
| 137/2 | 0.06 |
| 120 | 0.07 |
| 1408 | 0.05 |
| 119 | 0.03 |
| 118 | 0.03 |
| 159 | 0.07 |
| 117 | 0.15 |
| 1406 | 0.10 |
| 115/1 | 0.07 |
| 133 | 0.01 |
| 144 | 0.02 |
| 134 | 0.06 |
| 137/1 | 0.01 |
| 131 | 0.05 |

| (1) | (2) |
|--------|------|
| 140 | 0.10 |
| 141 | 0.04 |
| 142 | 0.02 |
| 155 | 0.02 |
| 194/2 | 0.12 |
| 194/3 | 0.14 |
| 169 | 0.02 |
| 170 | 0.03 |
| 176 | 0.04 |
| 1117 | 0.06 |
| 1118/1 | 0.02 |
| 1037/1 | 0.02 |
| 1116/2 | 0.05 |
| 1073 | 0.15 |
| 1387 | 0.11 |
| 1111 | 0.03 |
| 1092/2 | 0.07 |
| 1093 | 0.01 |
| 1084 | 0.04 |
| 1075 | 0.08 |
| 1076 | 0.05 |
| 1056 | 0.01 |
| 1054 | 0.03 |
| 1055 | 0.01 |
| 1049 | 0.07 |
| 194/1 | 0.12 |
| 1035 | 0.01 |
| 1034 | 0.02 |
| 1033/2 | 0.08 |
| 1411 | 0.12 |
| 1032 | 0.02 |
| 1381 | 0.19 |
| 1388 | 0.14 |
| 1395/1 | 0.05 |
| 1407 | 0.11 |
| 1444 | 0.04 |
| 1443 | 0.05 |
| 1496 | 0.04 |
| 1493 | 0.02 |
| 1492 | 0.12 |
| 1380 | 0.35 |
| 1394/3 | 0.02 |
| 1042 | 0.01 |

| (1) | (2) |
|--------|------|
| 1040 | 0.13 |
| 1037/4 | 0.03 |
| 1036 | 0.03 |
| 153 | 0.04 |
| 1445 | 0.01 |
| योग | 4.32 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमनेर मोती नाला व्यपवर्तन के शाखा नहर में भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 214/प्र.1/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.47 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 3 | 0.13 |
| 10 | 0.16 |
| 16 | 0.02 |
| 18 | 0.04 |
| 62 | 0.06 |
| 85 | 0.06 |
| 87 | 0.05 |
| 140 | 0.06 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------|------|--|-------|
| 13 | 0.43 | 86/4 | 0.08 |
| 14 | 0.07 | | |
| 59 | 0.15 | योग | 10.47 |
| 15 | 0.05 | | |
| 60 | 0.10 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तांदुला जल | |
| 58 | 0.16 | संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत पचपेड़ी जलाशय नहर निर्माण | |
| 29 | 0.13 | हेतु. | |
| 19 | 0.68 | (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) | |
| 21 | 0.16 | पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है. | |
| 90 | 0.49 | | |
| 22 | 0.40 | | |
| 23 | 0.07 | दुर्ग, दिनांक 15 फरवरी 2005 | |
| 39 | 0.09 | | |
| 24 | 1.38 | क्रमांक 214/प्र.1//2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का | |
| 25 | 0.08 | समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि | |
| 26 | 0.02 | की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए | |
| 27 | 0.03 | आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् | |
| 28, 38 | 0.11 | 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि | |
| 30 | 0.20 | उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— | |
| 31/1 | 0.04 | | |
| 31/2 | 0.10 | | |
| 35 | 0.07 | | |
| 54 | 0.05 | | |
| 55/3 | 0.05 | | |
| 68 | 0.17 | | |
| 61 | 0.43 | | |
| 65 | 0.28 | | |
| 63 | 0.34 | | |
| 64 | 0.12 | | |
| 82 | 0.89 | | |
| 86/1 | 0.24 | | |
| 86/2 | 0.07 | | |
| 86/3 | 0.08 | | |
| 91 | 0.49 | | |
| 92 | 0.31 | | |
| 93 | 0.07 | | |
| 137 | 0.19 | | |
| 138 | 0.17 | | |
| 139 | 0.19 | | |
| 36 | 0.07 | | |
| 37 | 0.32 | | |
| 88/1 | 0.12 | | |
| 88/2 | 0.12 | | |
| 67 | 0.03 | | |

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-धर्मी, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

623

0.24

633

0.08

637

0.07

640

0.04

641

0.10

643

0.05

658

0.04

659

0.04

660

0.02

661

0.02

662

0.02

| (1) | (2) |
|-----|------|
| 663 | 0.04 |
| योग | 0.75 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत पचपेड़ी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 214/प्र.1//2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-नाहंदा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 46 | 0.05 |
| 65/1 | 0.16 |
| 290 | 0.10 |
| 295 | 0.18 |
| 296 | 0.07 |
| 297 | 0.14 |
| 330/1 | 0.03 |
| 331/1 | 0.03 |
| 330/2 | 0.03 |

| (1) | (2) |
|-----|-------|
| 333 | 0.02 |
| योग | 0.081 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत नाहंदा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 214/प्र.1//2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-मटिया, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.34 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 135 | 0.09 |
| 134 | 0.03 |
| 132 | 0.26 |
| 145 | 0.01 |
| 153 | 0.01 |
| 154/1 | 0.10 |
| 118 | 0.08 |
| 51 | 0.02 |
| 119 | 0.04 |
| 120/2 | 0.04 |

(1)

(2)

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

| | |
|----------|------|
| 121 | 0.02 |
| 113 | 0.02 |
| 120/3 | 0.06 |
| 42/1 | 0.13 |
| 120/1 | 0.06 |
| 42/2 | 0.06 |
| 43 | 0.06 |
| 47 | 0.07 |
| 48 | 0.02 |
| 50 | 0.02 |
| 61 | 0.10 |
| 62 | 0.07 |
| 63 | 0.01 |
| 67 | 0.08 |
| 66 | 0.05 |
| 68 | 0.12 |
| 290 | 0.06 |
| 289 | 0.08 |
| 288/1- 2 | 0.02 |
| 288/7 | 0.06 |
| 288/4 | 0.02 |
| 287/1 | 0.02 |
| 287/2 | 0.06 |
| 287/3 | 0.06 |
| 286/2 | 0.01 |
| 286/1 | 0.03 |
| 279/1 | 0.19 |
| 255 | 0.02 |
| 256 | 0.04 |
| 257 | 0.04 |

योग

2.34

क्रमांक 434/प्र-1//भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-धमधा

(ग) नगर/ग्राम-भाठाकोकड़ी, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

| | |
|-------|------|
| 282/1 | 0.08 |
| 291/2 | 0.03 |
| 289 | 0.02 |
| 297 | 0.04 |
| 296 | 0.01 |
| 299 | 0.05 |
| 302 | 0.04 |
| 305 | 0.03 |
| 304 | 0.04 |
| 315/1 | 0.02 |
| 477 | 0.06 |
| 479/1 | 0.05 |
| 479/3 | 0.04 |
| 432 | 0.04 |
| 288 | 0.04 |
| 301 | 0.03 |
| 295 | 0.01 |
| 433 | 0.04 |
| 290 | 0.01 |
| 300 | 0.03 |
| 291/1 | 0.04 |
| 310 | 0.06 |
| 303 | 0.03 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत जोगनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

| (1) | (2) |
|-------|------|
| 306 | 0.06 |
| 319 | 0.08 |
| 478 | 0.05 |
| 479/2 | 0.04 |
| 481 | 0.08 |
| योग | 1.15 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमनेर मोती नाला व्यपवर्तन के नहर नाली के लिये अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 437/प्र-1//भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-घोठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 21/2 | 0.06 |
| 25 | 0.04 |
| 30 | 0.08 |
| 35 | 0.01 |
| 31 | 0.03 |
| 48/2 | 0.02 |
| 52 | 0.10 |

| (1) | (2) |
|------|------|
| 24 | 0.05 |
| 22 | 0.04 |
| 48/1 | 0.06 |
| 26 | 0.01 |
| 34 | 0.28 |
| 27 | 0.08 |
| 33 | 0.14 |
| 32 | 0.03 |
| 49 | 0.04 |
| 57/2 | 0.03 |
| 57/1 | 0.01 |
| योग | 1.11 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमनेर मोती नाला व्यपवर्तन के नहर नाली के लिये अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 440/प्र-1//भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-राजपुर, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.27 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 775 | 0.04 |

| (1) | (2) |
|-------|------|
| 896 | 0.08 |
| 945/2 | 0.01 |
| 921/1 | 0.02 |
| 945/5 | 0.02 |
| 917/1 | 0.03 |
| 912 | 0.08 |
| 827/4 | 0.20 |
| 428/4 | 0.12 |
| 782/3 | 0.03 |
| 925 | 0.01 |
| 945/6 | 0.02 |
| 921/3 | 0.05 |
| 961/2 | 0.02 |
| 917/2 | 0.04 |
| 913 | 0.12 |
| 451/1 | 1.28 |
| 920/1 | 0.02 |
| 894 | 0.10 |
| 922 | 0.08 |
| 924 | 0.06 |
| 944 | 0.11 |
| 946 | 0.14 |
| 915 | 0.16 |
| 914 | 0.01 |
| 427/1 | 0.20 |
| 916/3 | 0.02 |
| 895 | 0.12 |
| 926/4 | 0.01 |
| 923 | 0.08 |
| 945/4 | 0.02 |
| 928 | 0.01 |
| 824 | 0.02 |
| 825 | 0.42 |
| 428/6 | 0.10 |
| 429/1 | 0.42 |
| योग | 4.27 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राजपुर जलाशय के नहर नाली के लिये अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 15 मार्च 2005

क्रमांक/542/भू-अर्जन/अ.वि.अ./21-अ/82 सन् 2003-2004.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-खुर्सीपार, प. ह. नं. 40

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

428, 429, 462

1.47

योग

1

1.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सिरको जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 मार्च 2005

क्रमांक/543/भू-अर्जन/अ.वि.अ./53-अ/82 सन् 2003-2004.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(2)

क्रमांक/544/भू-अर्जन/अ.वि.अ./17-अ/82 सन् 2003-2004. — चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

| | | (1) | (2) |
|---------------------------------------|----------------|------|---------|
| (1) भूमि का वर्णन- | | 1076 | 0.04 |
| (क) जिला-महासमुन्द | | 653 | 0.05 |
| (ख) तहसील-महासमुन्द | | 680 | 0.16 |
| (ग) नगर/ग्राम-झिटकी, प. ह. नं. 112/59 | | 687 | 0.04 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.56 हेक्टेयर | | 651 | 0.28 |
| खसरा नम्बर | रकबा | 681 | 0.12 |
| | (हेक्टेयर में) | 688 | 0.05 |
| (1) | (2) | 961 | 0.02 |
| 601 | 0.02 | 1079 | 0.05 |
| 602 | 0.05 | 983 | 0.01 |
| 600 | 0.08 | 990 | 0.38 |
| 627 | 0.01 | 972 | 0.11 |
| 962 | 0.09 | 970 | 0.10 |
| 604 | 0.16 | 991 | 0.10 |
| 964 | 0.02 | 939 | 0.20 |
| 603 | 0.12 | 946 | 0.20 |
| 963 | 0.04 | 880 | 0.01 |
| 944 | 0.03 | 879 | 0.03 |
| 628 | 0.14 | 949 | 0.40 |
| 626 | 0.01 | 878 | 0.19 |
| 616 | 0.02 | 1075 | 0.04 |
| 618 | 0.05 | | |
| 615 | 0.03 | | |
| 619 | 0.06 | | |
| 620/2 | 0.03 | योग | 54 4.56 |
| 620/1 | 0.02 | | |
| 617 | 0.01 | | |
| 621 | 0.02 | | |
| 968 | 0.08 | | |
| 967 | 0.07 | | |
| 971 | 0.03 | | |
| 614 | 0.01 | | |
| 989 | 0.01 | | |
| 610 | 0.24 | | |
| 654 | 0.06 | | |
| 685 | 0.01 | | |
| 1078 | 0.04 | | |
| 965 | 0.10 | | |
| 652 | 0.17 | | |
| 679 | 0.05 | | |
| 686 | 0.10 | | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपर-जॉक परियोजना के माइनर क्र. 5 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक/568/भू-अर्जन/अ.वि.अ./52-अ/82 सन् 2003-2004. —चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

| अनुसूची | | (1) | (2) |
|-------------------------------------|------------------------|---|------|
| (1) भूमि का वर्णन- | | 2/11 टु. | 0.17 |
| (क) जिला-महासमुन्द | | 2/10 टु. | 0.16 |
| (ख) तहसील-महासमुन्द | योग | | 0.95 |
| (ग) नगर/ग्राम-मालीडीह, प. ह. नं. 04 | | | |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.95 हेक्टेयर | | | |
| | | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोडार परियोजना के अंतर्गत मालीडीह माइनर के निर्माण हेतु. | |
| | | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है. | |
| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) | (3) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. | |
| (1) | (2) | | |
| 2/2 टु. | 0.62 | | |

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6346/दो-2-63/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर को दिनांक 20-11-2002 से दिनांक 23-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19-11-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 24-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव को रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6525/दो-14-45/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 4-7-2001 से दिनांक 5-7-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. एस. नायर को डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. एस. नायर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6527/दो-14-45/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 27-9-2001 से दिनांक 1-10-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. एस. नायर को डिप्टी रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. एस. नायर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6529/दो-14-45/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 18-12-2001 से दिनांक 31-12-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 14 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16-12-2001 व 17-12-2001 एवं पश्चात् में दिनांक 1-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. एस. नायर को डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. एस. नायर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6531/दो-14-25/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 13-5-2002 से दिनांक 7-6-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 26 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11-5-2002 व 12-5-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 8-6-2002 व 9-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. एस. नायर को डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. एस. नायर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6533/दो-14-45/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 16-8-2002 से दिनांक 23-8-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15-8-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 24-8-2002 व 25-8-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. एस. नायर को डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. एस. नायर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4510/दो-2-34/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. सी. यदु, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 28-10-2003 से दिनांक 31-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25, 26 एवं 27-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री टी. सी. यदु को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. सी. यदु उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+11 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4508/दो-2-36/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अत्या. निवा.) अधिनियम दुर्ग को दिनांक 20-10-2003 से दिनांक 24-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19-10-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 25-10-2003 एवं 26-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+4 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4506/दो-2-36/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 16-10-2003 से दिनांक 19-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4572/तीन-6-8/2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री एस. एल. चक्रधारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर जिला सर्गुजा को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है।

No. 4572/III-6-8/2003.— In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri S. L. Chakradhari, Judicial Magistrate First Class, Ambikapur, District Surguja to try in a summary way all or any of the offences specified in the said section.

बिलासपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2003

क्रमांक 4751/दो-2-40/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुवीर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर को दिनांक 20-10-2003 से दिनांक 24-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19-10-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 25-10-2003 से 27-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुवीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 239 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2003

क्रमांक 5030/दो-2-32/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा, को दिनांक 24-11-2003 से दिनांक 29-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23-11-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 30-11-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 213 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2003

क्रमांक 5032/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. एक्ट) राजनांदगांव को दिनांक 27-11-2003 से दिनांक 29-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26-11-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 30-11-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो वे अपने पद पर कार्यरत रहतीं।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 16 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2003

क्रमांक 5028/दो-2-32/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को दिनांक 13-10-2003 से दिनांक 18-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12-10-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 19-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 219 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5286/दो-2-36/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) दुर्ग को दिनांक 18-11-2003 से दिनांक 19-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 238 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5288/दो-2-26/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एस. शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) बस्तर स्थान जगदलपुर को दिनांक 3-11-2003 से दिनांक 7-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2-11-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 8-11-2003 एवं 9-11-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 232+10 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5634/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 10-11-2003 से दिनांक 15-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16-11-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 219 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5636/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 13-10-2003 से दिनांक 15-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11-10-2003 एवं 12-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 225 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5638/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 5-9-2003 से दिनांक 10-9-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 228 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5640/दो-2-40/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुवीर सिंह, विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज, अंबिकापुर को दिनांक 2-9-2003 से दिनांक 12-9-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 11 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13-9-2003 एवं 14-9-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुवीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+4 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5642/दो-2-19/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जी. सी. बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुना को दिनांक 11-8-2003 से दिनांक 16-8-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9-8-2003 एवं 10-8-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 17-8-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. सी. बाजपेयी को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. सी. बाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+9 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5645/दो-2-28/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रंगनाथ चन्द्राकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 26-12-2003 से दिनांक 30-12-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25-12-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रंगनाथ चन्द्राकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रंगनाथ चन्द्राकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 235 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5647/दो-2-20/2003.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री बी. आर. निकुंज, विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. एक्ट) बिलासपुर को दिनांक 26-12-2003 से दिनांक 01-01-2004 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25-12-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. निकुंज को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. निकुंज उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 190 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5649/दो-2-20/2003.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री बी. आर. निकुंज, विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. एक्ट) बिलासपुर को दिनांक 20-10-2003 से दिनांक 24-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25-10-2003 एवं 26-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. निकुंज को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. निकुंज उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 197 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5651/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. भट्ट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 2-12-2003 से दिनांक 5-12-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. भट्ट को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+11 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5653/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. भट्ट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 19-11-2003 से दिनांक 20-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. भट्ट को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 320 दिवस का अर्ध वेतन अवकाश शेष है।

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5655/दो-2-22/2003.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती निर्मला सिंह, विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. एक्ट) अंबिकापुर को दिनांक 04-12-2003 से दिनांक 12-12-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13-12-2003 एवं 14-12-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निर्मला सिंह को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निर्मला सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो वे अपने पद पर कार्यरत रहतीं।

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 4 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

Bilaspur, the 8th-December 2003

No. 395/II-15-66/2001/Confdl./2003.— In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Shri Binay Kumar Shrivastava, Member of Higher Judicial Service presently posted as Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, as the Director of Judicial Officers Training Institute on the establishment of the High Court in addition to his present post of Registrar General from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 12th December 2003

No. 398/II-2-90/2001/Confdl./2003.— In exercise of the powers conferred by Article 229 (2) of the Constitution of India and Rule 20 of the Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003 framed thereunder, the Hon' ble the Chief Justice has been pleased to grant extension beyond the age of 60 years and up to 31-12-2005 to Shri Binaya Kumar Shrivastava, the Registrar General and the Director of Judicial Officers Training Institute on the establishment of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
T. K. JHA, Registrar (Vigilance).
